

एक नजर

गोरखपुर दंगे की सीबीआई जांच की याचिका पर सुनवाई आज

इलाहाबाद : गोरखपुर में 2007 में हुए सांप्रदायिक दंगों की सीबीआई जांच की मांग के लिए दाखिल जनहित याचिका की सुनवाई 28 जुलाई को होगी। याची परदेज पराजान और राज्य सरकार की तरफ से हलफनामे दाखिल किए गए। कोर्ट ने दोनों पक्षों की सहमति से शुक्रवार से सुनवाई शुरू करने का आदेश दिया। याचिका की सुनवाई न्यायमूर्ति वृष्ण मुरारी तथा न्यायमूर्ति अखिलेश चंद्र शर्मा की खंडपीठ कर रही है। याचिका पर अधिवक्ता एसएफएए नकवी तथा राज्य सरकार की तरफ से अपर महाधिवक्तागण अजय कुमार मिश्र, विनोद कांत, मनोष गोयल व अपर शासकीय अधिवक्ता एके संड ने पक्ष रखा। याचिका में दंगों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, गोरखपुर की मेयर व अन्य भाजपा नेताओं की लिखित याचिका आरोप लगाते हुए सीबीआई जांच की मांग की गई है। सीबीआई जांच की आरोप पत्र दाखिल कर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर अभियोग चलाने की संसृति मांगी थी, लेकिन गृह सचिव ने अनुमति देने से इनकार कर दिया। इस आदेश को भी याचिका में चुनौती दी गई है।

दाई सौ बीघे शत्रु संपत्ति के अभिलेख गायब
मुसदाबाद : करोड़ों रुपये की शत्रु संपत्तियों पर कब्जा है। जागरण ने शत्रु संपत्तियों से संबंधित कई मामलों का उजागर किया है। ताजा मामले में अभिलेखागार की जित्द से कागजों को फाड़कर दाई सौ बीघे शत्रु संपत्ति के दस्तावेज गायब कर दिए गए। एक साल पहले 53 फाईल गायब होने का मामला पकड़ में आया था। आठ माह तक चली जांच के बाद 45 फाइलें मिल गई थीं। अब अभिलेखागार की जित्द से पन्ने फाड़ भूमिफिया को फायदा पहुंचाने की कोशिश की गई। लखनऊ स्थित कार्यालय के सहयोग शत्रु संपत्ति अभिरक्षक पीएन श्रीनिवास ने दो जून 2017 को डीएम को पत्र भेजकर उचित कार्रवाई के लिए कहा था। अपर सिटी मैजिस्ट्रेट ने एडीएम प्रशासन को सीपी जांच रिपोर्ट में अभिलेखों के गायब होने की पुष्टि की है। एडीएम प्रशासन लक्ष्मीशंकर ने बताया कि चकबंदी के दौरान अभिलेखागार के दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ की गई है। जित्द से कागज फटने के साथ ही गायब होने की जांच कराई गई है, जिसमें एक बाबू की कार्यपालनी को संदिग्ध पाया गया है। जल्द कार्रवाई की जाएगी।

दादी बढ़ाने पर छत्र को कालेज से निकाला
बाणपत : खेकड़ा थाना क्षेत्र के स्टडी स्थित सेंट मैरी इंटर कालेज में शिक्षक ने 11वीं के छात्र सद्म को दादी कटाकर आने पर दबाव बनाया। आरोप है कि शिक्षक ने अभद्रता व जातिभेद के शब्दों का प्रयोग किया। साथ ही उसे कक्षा के साथ कालेज से भी बाहर निकाल दिया। इस पर उसके परिजनों ने कालेज में हंगामा करते हुए शिक्षक को जमकर खरीखोटी सुनाई। आरोपी शिक्षक के खिलाफ तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की। प्रधानाचार्य ने परिजनों के आरोप को सिरे से खारिज किया है। कालेज प्रधानाचार्य रविंद्र सिंह की कहना है कि उक्त शिक्षक ने उनके सामने ही छात्र को सिर के बाल कटवाने की हिदायत दी थी। दादी के बाल कटवाने का आरोप सरासर गलत है।

सुपारी से कैसर पर केंद्र ने एनआइसीपीआर से मांगी रिपोर्ट

धर्मरंज मिश्रा, नोएडा
 सुपारी से होने वाले कैसर को केंद्र सरकार ने बेहद गंभीरता से लेते हुए राष्ट्रीय कैसर रोकथाम व नियंत्रण संस्थान (एनआइसीपीआर) से एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने को कहा है। अब जल्द ही एनआइसीपीआर देश भर में सुपारी के इस्तेमाल व इसके दुष्प्रभाव पर सर्वे शुरू करने की योजना तैयार कर रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) व दुनिया की कई अन्य संस्थाएं कई वर्ष पहले ही सुपारी से कैसर होने का दावा कर चुकी हैं। भारत में भी इस पर कई शोध हो

जल्द ही देश भर में सुपारी चबाने वालों पर शुरू होगा सर्वे, शोध में सुपारी चबाने से कैसर होने की बात आ चुकी है सामने
 चुके हैं, लेकिन अभी तक देश में सुपारी खाने वालों की वास्तविक संख्या, कारण व इसके दुष्प्रभाव पर कोई सटीक व प्रमाणिक जानकारी नहीं है। यहां तक कि इसके दुष्प्रभावों को रोकने के लिए कोई गाइडलाइन या कानून तक नहीं बनाया गया है। एनआइसीपीआर व एम्स के विशेषज्ञों के अनुसार सुपारी व पान मसाला भी कैसर के बड़े कारणों में से एक है।



एक्लेलाइड व पोलीफिनोले हैं कैसर कारक : हमारे देश में शादी समारोह, शगुन के सभी कार्यक्रम व अन्य खुशी के मौकों

दुनिया भर के कई शोध में सुपारी से कैसर होने की बात सामने आ चुकी है, लेकिन इसे लेकर अभी देश में उत्तरी जागरूकता नहीं है। केंद्र सरकार ने इसलिए एनआइसीपीआर से इस पर विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने को कहा है, ताकि इससे होने वाले कैसर को रोका जा सके। डॉ. रवि मेहरोत्रा, निदेशक एनआइसीपीआर

राज्यपाल ने कहा, पूर्व राष्ट्रपति एक सैनिक की तरह ही हुए शहीद

डॉ. अब्दुल कलाम ने ज्ञान बांटते बांटते दी शहादत : राम नाईक

एकेटीयू
जागरण संवाददाता, लखनऊ : पूर्व राष्ट्रपति डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम ने ज्ञान बांटते-बांटते ही शहादत दी। वह एक सैनिक की तरह शहीद हुए। आइए हम शिलांग में भाषण देते हुए उनकी तबीयत बिगड़ी और फिर मृत्यु हो गई। उन्होंने देश को परमाणु शक्ति दी और बेहतरीन ढंग से वैज्ञानिक नेतृत्व किया। यही कारण है कि किसी राजनीतिक दल से संबंध न होने के बावजूद भी उन्हें राष्ट्रपति बनाया गया। यह विचार राज्यपाल राम नाईक ने व्यक्त किए। वह गुरुवार डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय (एकेटीयू) में डॉ. कलाम की दूसरी पुण्यतिथि के मौके पर आयोजित इंटरनेशनल यूथ कॉन्क्लेव में उपस्थित लोगों को संबोधित कर रहे थे। 'पृथ्वी को जीवन जीने लायक बनाने में भाग्य जाति का योगदान' विषयक कॉन्क्लेव में उन्होंने डॉ. कलाम स्मारक में डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम व अन्य प्रसिद्ध



लखनऊ : डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विधि में डॉ. कलाम की दूसरी पुण्यतिथि के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार को सम्मानित करते राज्यपाल रामनाईक, प्राविधिक शिक्षामंत्री आशुतोष टंडन व अन्य जागरण

ने विद्यार्थियों का आह्वान किया कि वह जांब दूढ़ने वाले न बनें बल्कि जांब देने वाले बनें। कार्यक्रम में जिन तीन विद्यार्थियों की टीम को अलग-अलग स्टार्टअप शुरू करने के लिए दस-दस लाख रुपये दिए गए। उनमें आइआइटी वीएचयू के रोहित कुमार मित्तल व नवीन कुमार की टीम जिसने पानी साफ करने में बहुत कम पानी बर्बाद होने का मॉडल इजाद किया है। वहीं दूसरी टीम जिसमें मानवेंद्र यादव व सुधांशु आदि शामिल हैं। इन्होंने राइस थ्रेशर मशीन बनाई है जो एक मिन्ट में पांच किलो धान कूटती है। इसके अलावा प्रणय वाल व गोपाल त्रिवेदी की टीम जिसने मधुमेह से शरीर की नसों को हों रहे नुकसान का आकलन करने वाली डिवाइस इजाद की है। कार्यक्रम में सुपर 30 के फाउंडर आनंद कुमार, आदि चतुर्चक्रिण मठ के प्रमुख श्री श्री निर्मलानंदनाथ महाशायमी, विज्ञान भारती के संगठन मंत्री जयंत सहर्षबुद्धे और भाजपा के विधायक पंकज सिंह मौजूद रहे।

दारुल उलूम में तलवा के स्मार्ट फोन पर पाबंदी

जासं, देवबंद : प्रसिद्ध इस्लामी तालीमी इदारा दारुल उलूम देवबंद ने तलवा (छात्र) के लिए स्मार्ट फोन पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी है। प्रबंधन के मुताबिक, तालीमी की बेहतरी के लिए यह कदम उठाया गया है। दारुल उलूम द्वारा जारी हिदायतनामे में यह भी चेतावनी दी गई है कि स्मार्ट फोन पर मुकम्मल पाबंदी लगाई जाती है। दारुल उलूम का मकसद बच्चों को तालीमीयाफता के साथ ही संस्कार बनाना भी है। फिल्टर, सिनेमा, क्रिकेट देखने और इंटरनेट पर गैर जरूरी साइट देखने वाले तलवा को शिक्षा से वंचित कर दिया जाएगा। कैमरे वाले और फ्रीजर वाले मोबाइल फोन रखना ज़ुर्म होगा। अलबत्ता जरूरी बातचीत के लिए तलवा सादा फोन रख सकते हैं।

सिर्फ एक गोली से घातक हेपेटाइटिस सी का इलाज

रणविजय सिंह, नई दिल्ली
 हर साल हजारों लोगों की मौत का कारण बन रहे हेपेटाइटिस सी अब जानलेवा नहीं बनेगा। इस बीमारी की अस्तरदार दवाएं उपलब्ध होने के बाद मरीजों के लिए अब इलाज और आसान हो गया है, क्योंकि नई दवाओं को कंबाईंड डोज की गोली भी उपलब्ध हो गई है। इस कंबाईंड डोज की एक गोली से हेपेटाइटिस सी के मरीज का इलाज संभव है। इसका फायदा यह है कि मरीजों को दो-तीन तरह की दवाएं लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा इलाज भी सस्ता हो गया है। एम्स में हुए एक अध्ययन में यह बात सामने आई है कि भारतीय जनिक दवाएं भी 95 फीसद तक इलाज में अस्तरदार हैं। देश में करीब 1.20 करोड़ लोग इस बीमारी से पीड़ित हैं। रक्त में संक्रमण के कारण यह बीमारी होती है। इस बीमारी का शुरुआत में पता नहीं चल पाता। इस

सिंगल विंडो को प्रभावी तरीके से लागू कराएं : मुख्य सचिव

रायू, लखनऊ : मुख्य सचिव राजीव कुमार ने निर्देश दिये हैं कि प्रदेश में उद्यमियों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने के लिए लागू सिंगल विंडो सिस्टम को सुदृढ़ कर प्रभावी ढंग से क्रियान्वित कराया जाए। उन्होंने समस्त मंडलायुक्तों व जिलाधिकारियों को मंडलीय व जिला स्तर पर तब समर्थ-सारिणी के अनुसार उद्योग बंधु की बैठके नियमित रूप से आयोजित करने का निर्देश दिया है। मुख्य सचिव गुरुवार को सिंगल विंडो सिस्टम को प्रभावी तरीके से लागू करने के बारे में अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कुछ विभागों ने समन्वय के लिए राज्य और जिला स्तर पर अभी तक नोडल अधिकारी नामित नहीं किये हैं। वह तत्काल नोडल अधिकारी नामित कर उद्योग बंधु को अवगत कराएं।

8700 ग्रेड पे वाले अफसरों का वेतन बढ़ा

रायू, लखनऊ : सातवें वेतनमान की पुनरीक्षित मैट्रिक्स में लेवल-13 (ग्रेड पे 8700 रुपये) में शामिल राज्य सरकार के अफसरों का वेतन बढ़ गया है। केंद्र सरकार की अधिसूचना के क्रम में राज्य सरकार ने भी लेवल-13 को संशोधित करने का शासनदेश गुरुवार को जारी कर दिया है। इस संशोधन के कारण लेवल-13 में शामिल सरकारी अफसरों का वेतन 4600 से 8000 रुपये तक बढ़ जाएगा। सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को मानते हुए राज्य सरकार ने 20 दिसंबर 2016 को राज्य कर्मचारियों के लिए पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स को स्वीकृति दी थी। पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में ग्रेड पे 8700 रुपये के लिए लेवल-13 निर्धारित था।

शिक्षित और हुनरमंद बनेंगे बुनकर कपड़ा मंत्रालय ने की पहल

प्रभात उपाध्याय, नोएडा
 देशभर में बुनकरों को शिक्षित और हुनरमंद बनाने के लिए केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय ने पहल की है। इसका जिम्मा एनआइओएस (नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग) को सौंपा है। अगले महीने गुवाहाटी से इसकी शुरुआत होगी। एनआइओएस स्कूली शिक्षा से वंचित विभिन्न राज्यों के बुनकरों को 10वीं और 12वीं की शिक्षा देगा। साथ-साथ ही बुनकरों को उनके क्षेत्र में दक्ष भी बनाएगा। इसके लिए 10वीं-12वीं का विशेष पाठ्यक्रम तैयार किया गया है। अधिकारियों ने बताया कि बुनकर समुदाय में एससी, एसटी और महिला वर्ग के अभ्यर्थियों की पूरी शिक्षा निशुल्क होगी। फीस आदि का 75 फीसद खर्च मंत्रालय उठाएगा, जबकि 25 फीसद एनआइओएस सब्सिडी के तौर पर देगा। वहीं बीपीएल कोटे के अभ्यर्थियों को 25 फीसद फीस खुद देनी होगी। वाराणसी में खुलेगा विशेष केंद्र : बुनकरों के पठन-पाठन के लिए विशेष केंद्र भी खोले जाएंगे। एनआइओएस के अधिकारियों ने बताया कि प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में केंद्र के लिए जगह चिन्हित की जा रही है। क्योंकि वहां पहले ही सर्वे के माध्यम से करीब आठ बुनकरों को चुना गया है। जबकि, अन्य राज्यों में केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय के हैडलूम क्लस्टर में केंद्र बनाए जाएंगे। दाखिला दिलाने के लिए सर्वेयर होंगे तेनात : बुनकरों के पठन-पाठन के लिए एनआइओएस देशभर में सर्वेयर भी तेनात करेगा। बुनकरों का चयन कर एनआइओएस में पंजीकरण करने की जिम्मेदारी उन्हीं की होगी। एसा होगा कोर्स : एनआइओएस ने बुनकरों के लिए विशेष पाठ्यक्रम भी तैयार किया है। 10वीं या 12वीं में दाखिला लेने वाले किसी भी बुनकर को कुल पांच विषय पढ़ने होंगे। इसमें से तीन विषय उनके पेशे से जुड़े होंगे, जबकि एक विषय कपड़ा उद्योग में उद्यमिता (एंटरप्रेनोरशिप) का और एक भाषा का होगा।

इंटर कालेजों में 50 फीसद पद प्रोन्नति से भरने को चुनौती

विर्स, इलाहाबाद : प्रदेश के इंटर कालेजों में 50 फीसद पद प्रोन्नति कोटे से भरने को एक याचिका में चुनौती दी गई है। इस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रमुख सचिव से जवाब मांगा है। याचिका पर अगली सुनवाई आठ अगस्त को होगी। कोर्ट ने कहा है कि यह गंभीर मुद्दा है इसलिए विस्तृत जवाबी हलफनामा दाखिल किया जाए। यह आदेश न्यायमूर्ति अरुण टंडन और न्यायमूर्ति ऋतुगज अवस्थी की खंडपीठ ने अशफा लाल की याचिका पर दिया है। कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि क्या 50 फीसद प्रोन्नति कोटा वैध है? और यह अनुच्छेद 14 के समानता के अधिकार के विपरीत नहीं है?।

पीठासीन अधिकारियों की भर्ती न होने पर मांगा जवाब

विधि संवाददाता, इलाहाबाद : प्रदेश के श्रम न्यायालयों में पीठासीन अधिकारियों के खाली पद भरने की मांग संबंधी याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से तीन अगस्त तक जवाब मांगा है। यह आदेश न्यायमूर्ति अरुण टंडन तथा न्यायमूर्ति ऋतुगज अवस्थी की खंडपीठ ने चंद्रशेखर की याचिका पर दिया है। याची का कहना है कि श्रम न्यायालयों में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत न्यायिक अधिकारी ही पीठासीन अधिकारी नियुक्त हो सकते हैं। सरकार खाली पदों पर भर्ती नहीं कर रही है ऐसे में लोगों को न्याय नहीं मिल पा रहा है। स्थाई अधिवक्ता सोम नारायण मिश्र ने का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कानून में संशोधन किया गया है। सरकार खाली पदों को भरने के लिए शीघ्र कदम उठाने जा रही है।

JAGRAN INSTITUTE OF MANAGEMENT
 BUILDING | PROFESSIONAL | COMPETENCIES
 (An Autonomous Institute approved by AICTE, Ministry of HRD, Govt. of India)

AKTU Code : 434

PGDM MCA

Post Graduate Diploma in Management
2-Year Full Time Program

Master of Computer Application
3-Year Full Time Program

Admissions Open for 2017

ACADEMIC BRILLIANCE

- Most modern purpose built business school of Uttar Pradesh.
- Established under the benevolence & support of DAINIK JAGRAN.
- The campus environment conducive for professional grooming.

State of Art Infrastructure :

- Air conditioned class rooms equipped with Audio Video facilities.
- Wi-Fi Campus with 300+ work stations.
- Strong Industry Interface (Conferences, Seminars, Workshops)
- Experienced & Qualified Faculty
- Internship, Research projects & Industry Visits integral part of the course
- Curriculum endorsed by Industry experts

Specializations :

- Marketing
- Finance
- Human Resource
- International Business

PLACEMENT EXCELLENCE

INTERNATIONAL SYMPOSIUM

EXCURSION TRIP

SPORTS MEET

620, W Block, Juhu, Saket Nagar, Kanpur - 208 014

Phone: 0512- 2601126, 9935444524 (PGDM), 9307965698 (MCA)

www.jimkanpur.ac.in

भारत सरकार
वस्त्र मंत्रालय
हैंडलूम विकास आयुक्त का कार्यालय

संत कबीर पुरस्कार, राष्ट्रीय पुरस्कार एवं राष्ट्रीय मेरिट प्रमाण पत्र 2016

नीचे दर्शाए गए विवरण के अनुसार हैंडलूम सेक्टर के क्षेत्र में अपना उत्कृष्ट योगदान के लिए पुरस्कार की निम्नलिखित संख्यां हेतु भारतीय नागरिकों से निर्धारित प्राकृत में विभिन्न भरा हुआ आवेदन आमंत्रित किया जाता है:-

क्र. सं.	पुरस्कार का नाम	संवर्ग	पुरस्कारों की अधिकतम संख्या				
			सामान्य	कमलादेवी चट्टोपाध्याय अवार्ड्स' जैसे ज्ञात विशेषकर महिला हैंडलूम बुनकरों हेतु	योग	कुल योग	
01	संत कबीर पुरस्कार (SKA)	बुनाई	10	02	12	12	
		राष्ट्रीय पुरस्कार (NA)	हैंडलूम उत्पादों के प्रोत्साहन हेतु डिजाइन विकास	03	04	24	32
			हैंडलूम उत्पादों के विपणन	05	05		
03	राष्ट्रीय मेरिट प्रमाण पत्र (NMC)	बुनाई	20	04	24	40	
		हैंडलूम उत्पादों के प्रोत्साहन हेतु डिजाइन विकास	06	---	06		
		हैंडलूम उत्पादों के विपणन	10	---	10		
		योग	74	10	84	84	

2. पात्रता मानदंड, आयु, अनुभव आदि, विवरण के संबंध में विशेष जानकारी हैंडलूम के लिए विकास के कार्यालय की वेबसाइट (www.handlooms.nic.in) से डाउनलोड भी किया जा सकता है। आप किसी जानकारी/सहायता के लिए निकटतम बुनकर सेवा केंद्र या क्षेत्रीय निदेशक, बुनकर सेवा केंद्र से भी संपर्क कर सकते हैं।
 3. आवेदन निकटतम बुनकर सेवा केंद्र से प्राप्त किया जा सकता है अथवा हैंडलूम विकास आयुक्त के कार्यालय (www.handlooms.nic.in) से डाउनलोड भी किया जा सकता है।
 4. अर्पणित दस्तावेज/दस्ता-बुनाई नमूने के साथ सभी पक्षों से विधिवत परिपूर्ण आवेदन अधिकतम 21 अगस्त 2017 तक निकटतम बुनकर सेवा केंद्र में जमा किया जाना चाहिए।

विकास आयुक्त (हैंडलूम), उद्योग भवन, नई दिल्ली